बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 09 ● नई दिल्ली ● मंगलवार 14 अक्तूबर 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में सिलिंडर लीक होने पर तेज धमाका, दहल उठा पूरा इलाका और 5 लोग जख्मी

उत्तरी दिल्ली। उत्तरी दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में सोमवार सुबह एक मकान में एलपीजी सिलिंडर लिकेज होने के बाद तेज धमाका हुआ और फिर आग लग गई। हादसे में एक ही परिवार के पांच लोग जख्मी हो गए। बताया गया कि सुबह 9.29 बजे सूचना मिलने के बाद पुलिस के अलावा दमकल की दो गाड़ियां नई बस्ती, किशनगंज के मकान में पहुंचीं। हादसे में रसोई की दीवार गिर गई। घायलों को एंबुलेंस और पीसीआर की मदद से आरएमएल और एलएन अस्पताल भेजा गया। वहीं, अस्पताल में दो की हालत नाजुक बताई जा रही है। सब्जी मंडी थाना पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

शारदा घोटाला: सीबीआई पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पूछा- राजीव कुमार से 6 साल क्यों नहीं हुई पूछताछ?

नई दिल्ली ।

करोड़ों रुपये के शारदा चिटफंड घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार को दी गई अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर इस सप्ताह के अंत में सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने सोमवार को सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की जोरदार दलीलों पर गौर किया और मामले की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर के लिए तय कर दी। सॉलिसिटर जनरल ने दलील दी कि जांच एजेंसी की याचिका को अन्य लंबित याचिकाओं के साथ सूचीबद्ध किया जाए, जिसमें पूरे मामले की व्यापक समझ और विचार के लिए अवमानना याचिका भी शामिल है। पीठ ने सीबीआई की याचिका को अन्य लंबित मामलों के साथ शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध कर दिया। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को 1 अक्टूबर, 2019 को अग्रिम ज़मानत दी गई थी और उनके वकील के अनुसार, पिछले छह वर्षों में सीबीआई ने उन्हें एक बार भी पूछताछ के लिए नहीं बुलाया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हमें इस मामले को लंबित क्यों रखना चाहिए? आपने इतने वर्षों में कुछ नहीं किया। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस मामले में एक वरिष्ठ सीबीआई अधिकारी के आवास को गुंडों ने घेर लिया और उन्हें कोलकाता में अपने परिवार के सदस्यों की सलामती के लिए सचमुच मदद की गुहार लगानी पड़ी। मेहता ने अनुरोध किया कि दिवाली की छुट्टियों के बाद अन्य याचिकाओं पर भी एक साथ विचार किया जाए। जनवरी 2019 में, केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच अभूतपूर्व गतिरोध तब पैदा हो गया था जब सीबीआई की एक टीम कुमार से पूछताछ के लिए उनके आधिकारिक आवास पर पहुँची थी, लेकिन स्थानीय पुलिस द्वारा उनके अधिकारियों को हिरासत में लिए जाने के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कुमार के बचाव में आगे आईं और केंद्र के इस कदम के खिलाफ धरना शुरू कर दिया।

दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएफआई प्रतिबंध चुनौती को विचारणीय माना, केंद्र को नोटिस जारी

नई दिल्ली । दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत संगठन पर लगाए गए पांच साल के प्रतिबंध को बरकरार रखा गया था। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि यूएपीए ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश के खिलाफ याचिका पर विचार करने का अधिकार उसके पास है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने केंद्र से जवाब मांगा और सुनवाई की अगली तारीख 20 जनवरी तय की। अदालत ने पीएफआई की याचिका की विचारणीयता पर फैसला सुनाते हुए कहा तदनुसार, हम मानते हैं कि इस न्यायालय को संविधान के अनुछेद 226 के तहत न्यायाधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील पर विचार करने का अधिकार है। नोटिस जारी करें। 20/1 को सूचीबद्ध करें। फैसले की विस्तृत प्रति का इंतज़ार है। सितंबर 2022 में केंद्र ने पीएफआई और उसके सहयोगियों को गैरकानूनी घोषित कर दिया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रतिबंध लगाने के अलावा, पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों को कथित रूप से इस्लामी कट्टरपंथ और आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण आतंकवाद विरोधी कानून के तहत गैरकानूनी संघ के रूप में भी नामित किया था। दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा की अध्यक्षता वाले यूएपीए न्यायाधिकरण ने 21 मार्च, 2023 को इस प्रतिबंध की पुष्टि की। पीएफआई ने यूएपीए न्यायाधिकरण के मार्च

2023 के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने नवंबर 2023 में कहा था कि पीएफआई के लिए पहले उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना उचित होगा। केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने दलील दी थी कि पीएफआई की याचिका विचारणीय नहीं है क्योंकि यूएपीए न्यायाधिकरण दिल्ली उच्च न्यायालय के एक कार्यरत न्यायाधीश द्वारा संचालित है, और इसलिए इस आदेश को भारत के संविधान के अनुछेद 226 के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती। निश्चित रूप से संविधान का अनुछेद 226 उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और किसी अन्य उद्देश्य के लिए कुछ रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।

इस्कॉन उद्धार 2025 ने रचा इतिहास,15,000 युवाओं के साथ नशा मुक्ति में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

नई दिल्ली । नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित इस्कॉन के वार्षिक युवा उत्सव 'उद्धार 2025' ने इतिहास रचते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

यह उपलब्धि नशा मुक्ति अभियान में अब तक की सबसे बड़ी युवा भागीदारी के लिए दर्ज की गई. देशभर से लगभग 15,000 युवाओं ने इस आयोजन में हिस्सा लेकर समाज को नशामुक्त बनाने का संकल्प लिया.

संस्कृति और कल्याण की थीम ने दी नई दिशा

इस्कॉन द्वारा आयोजित यह वार्षिक उत्सव केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि युवा शक्ति के सामूहिक जागरण का प्रतीक बना. 'उद्धार 2025' को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया, जिसने भारत के युवाओं की जागरूकता और सकारात्मक ऊर्जा को नई पहचान दी. उद्धार मीडिया प्रमुख पदसेवन भक्त दास ने बताया कि, इस वर्ष कार्यक्रम की थीम संस्कृति और कल्याण रखी गई थी. इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे. इस मौके पर इस्कॉन जीबीसी के चेयरमैन गुरु प्रसाद स्वामी महाराज ने कहा कि भारत के युवाओं में अपार ऊर्जा है, जिन्हें केवल सही दिशा और मूल्य शिक्षा की आवश्यकता है.

आकर्षक प्रस्तुतियां और प्रेरक वक्ताओं ने बढ़ाया उत्साह

पदसेवन दास के मुताबिक, कार्यक्रम के आकर्षणों में 'क्रेजी हॉपर्स' समूह का जोशपूर्ण नृत्य प्रदर्शन, वाईएमसीए और दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा प्रस्तुत मूक अभिनय और अद्भुत ड्रोन शो शामिल रहे. इन प्रस्तुतियों ने नशा मुक्ति और आत्मविकास का संदेश रचनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया. कार्यक्रम में प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर डॉ. विवेक बिंद्रा, अमोघ लीला प्रभु, रुक्मिणी कृष्ण प्रभु और सुंदर गोपाल प्रभु ने युवाओं को नेतृत्व, आत्मविकास और जीवन मूल्यों पर प्रेरक विचारों से मार्गदर्शन दिया. लोकनाथ स्वामी महाराज के भक्ति-कीर्तन ने पूरे स्टेडियम में आध्यात्मिक उत्साह का वातावरण बना दिया. सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और मोटिवेशनल वक्ता कुलदीप सिंधानिया, सोनू शर्मा, आरजे रौनक, नितेश सोनी और अलख पांडे ने भी मंच साझा किया और युवाओं को अनुशासन, नशा मुक्ति और सकारात्मक सोच अपनाने के लिए प्रेरित किया.

छह साल से जारी नशा विरोधी जागरूकता अभियान

बताते चलें कि, इस्कॉन ने नशा विरोधी जागरूकता अभियान की शुरुआत 2019 में की थी. बीते छह वर्षों में देशभर के 100 से अधिक इस्कॉन केंद्रों के माध्यम से लगभग एक लाख युवा इस अभियान से जुड़ कर लाभ उठा चुके हैं और नशा मुक्त समाज के निर्माण की दिशा में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने गायिका नेहा राठौर को नहीं दी राहत, एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गायिका नेहा सिंह राठौर को राहत देने से इनकार कर दिया और उनकी याचिका खारिज कर दी। नेहा राठौर ने उनकी एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दर्ज एफआईआर को रद्द कराने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने नेहा राठौर की याचिका खारिज करते हुए उनसे कहा कि वे जाकर मुकदमे का सामना करें। शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वह मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं कर रही है। जस्टिस जे के माहेश्वरी और जस्टिस कुलदीप बिश्नोई की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस समय वह विद्रोह के आरोप (भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने) के मुद्दे में हस्तक्षेप नहीं कर रही है। नेहा राठौर ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 19 सितंबर के उस आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था जिसमें एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। नेहा सिंह राठौर ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भाजपा और पीएम मोदी पर टिप्पणी की थी। उनकी इस टिप्पणी के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में अप्रैल में एफआईआर दर्ज हुई थी। उन पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज हुआ। नेहा राठौर ने एक्स (ट्वि) पर पोस्ट किया था कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद मोदी बिहार आए ताकि पाकिस्तान को धमका सकें और राष्ट्रवाद के नाम पर वोट बटोर सकें। उन्होंने यह भी लिखा था कि आतंकियों को ढूंढने और अपनी गलती मानने के बजाय बीजेपी देश को युद्ध की तरफ धकेलना चाहती है। पुलिस ने नेहा राठौर के खिलाफ भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट कर भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने के आरोपों में मामला दर्ज किया। लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में अभय प्रताप सिंह नामक व्यक्ति ने नेहा राठौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। शिकायतकर्ता ने राठौर पर धार्मिक आधार पर एक समुदाय को दूसरे के खिलाफ भड़काने की बार-बार कोशिश करने का आरोप लगाया था।

एमसीडी के बजट में स्वच्छता, सड़क निर्माण और शिक्षा पर रहेगा जोर

नई दिल्ली । एमसीडी ने अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट की तैयारी की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू कर दी है। एमसीडी के वित्त विभाग ने इसके लिए विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया है जिसके तहत सभी विभागों के साथ बैठकें शुरू होंगी।

बजट में राजधानी की स्वच्छता, सड़क निर्माण और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि संपत्ति कर, विज्ञापन शुल्क, पार्किंग शुल्क, कनवर्जन चार्ज, टोल टैक्स और विभिन्न प्रकार के लाइसेंस शुल्क को बढ़ाया जा सकता है। इनमें कई वर्षों से बढ़ोतरी नहीं हुई है। साथ ही, खर्चों में कटौती और संसाधनों के कुशल प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। उसकी योजना है कि अनावश्यक खर्चों को सीमित किया जाए और उपलब्ध धन का अधिकतम उपयोग उन क्षेत्रों में किया जाए जिनका सीधा संबंध जनता की सुविधा और शहर के विकास से है। एक सप्ताह तक चलने वाली बैठकों में हर विभाग अपनी योजनाओं, खर्च के अनुमान और भविष्य की वित्तीय आवश्यकताओं की जानकारी देगा। एमसीडी का लक्ष्य है कि बजट तैयार करने से पहले सभी विभागों की प्राथमिकताएं और जरूरतें स्पष्ट हो जाएं ताकि अगले वित्तीय वर्ष में कामकाज समय पर शुरू किया जा सके। एमसीडी सूत्रों के मुताबिक, वित्त विभाग ने प्रत्येक विभाग को प्रस्तावित कार्यों, परियोजनाओं और उनके लिए अनुमानित धनराशि का ब्योरा प्रस्तुत करने को कहा है। यह जानकारी एमसीडी के समेकित बजट का आधार बनेगी। आयुक्त दिसंबर के पहले सप्ताह में बजट प्रस्ताव को

स्थायी समिति के समक्ष पेश करेंगे जिसके बाद उसे सदन में अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। इस बार एमसीडी का बजट केवल खर्च का दस्तावेज नहीं बल्कि सुधार और संसाधन-संतुलन का रोडमैप होगा। प्रशासन उम्मीद कर रहा है कि समय से पहले तैयारी और समन्वय से न सिर्फ राजस्व की स्थिति सुधरेगी बल्कि विकास कार्यों में भी तेजी आएगी।

स्वच्छता, सड़क और शिक्षा क्षेत्र को मिलेगी प्राथमिकता

एमसीडी के अनुसार, आगामी वर्ष के बजट में स्वच्छता व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। योजना है कि कूड़ा प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाया जाए, डोर-टू-डोर कलेक्शन सिस्टम को और मजबूत किया जाए और लैंडफिल स्थलों के कचरे के निपटान के कार्य को तेज किया जाए। सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों को भी बजट में अहम स्थान मिलेगा। बारिश के दौरान जलभराव की समस्या से निपटने के लिए जल निकासी तंत्र को दुरुस्त करने पर विशेष बल दिया जाएगा। साथ ही, पार्कों के रखरखाव और हरित क्षेत्रों के विस्तार को भी प्राथमिकता सूची में शामिल किया गया है।

स्मार्ट क्लासरूम की संख्या बढ़ेगी

शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी एमसीडी ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए बड़े लक्ष्य तय किए हैं। स्कूलों में आधारभूत ढांचे के सुधार, स्मार्ट क्लासरूम की संख्या बढ़ाने और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए अलग से बजट प्रावधान किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग को भी क्लीनिकों और अस्पतालों की सुविधाओं को उन्नत करने के लिए अतिरिक्त राशि आवंटित करने की योजना है।

राजस्व बढ़ाना और खर्च पर नियंत्रण

एमसीडी इस समय गंभीर वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रही है। पिछले वर्षों में राजस्व संग्रह में कमी के कारण कई विकास परियोजनाएं प्रभावित हुईं और नई नहीं बनाई जा रही हैं। इसे देखते हुए इस बार एमसीडी ने बजट प्रक्रिया के प्रारंभिक चरण में ही राजस्व बढ़ाने की दिशा में ठोस रणनीति बनाने का फैसला किया है।

तेजस्वी को मनोज झा की कमी क्यों खली?

त्रिदीब रमण

बिहार चुनाव का शंखनाद हो चुका है, एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए यह 'करो या मरो' वाला चुनाव है, सच पूछिए तो 2005 के विधानसभा चुनाव के कोई दो दशक बाद इस दफे के चुनाव में चुनावी मुद्दों की बात हो रही है, उनकी पड़ताल हो रही है। नहीं तो पिछले 20 सालों में यहां चुनाव जातीय व धार्मिक ध्रुवीकरण पर ही लड़ा जाता रहा है। इस दफे नीतीश-भाजपा ने तेजस्वी के महागठबंधन के समक्ष कई अवसर उछाले हैं, पर अबतलक राजद नेता उन मौकों को लपकने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। राहुल व सीपीआईएल नेता दीपंकर भट्टाचार्य दोनों को ऐसा लग रहा है कि 'तेजस्वी ने 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान जो सक्रियता व आक्रमकता दिखाई थी वह इस बार उनके चुनावी अभियानों से गायब है। क्या ऐसा महज उनके सारथी बदल जाने की वजह से हुआ है?' अब से पहले राज्यसभा सांसद मनोज झा तेजस्वी के दिल-दिमाग की तरह काम करते थे, उन्हें महत्वपूर्ण राजनीतिक फैसले लेने में मदद करते थे, पर इस दफे के चुनाव में मनोज झा परिदृश्य से ओझल हैं। सूत्र बताते हैं कि उनके पिता की तबियत खराब है, जो दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं, जहां मनोज अपने पिता को ही अपना पूरा वक्त दे रहे हैं, इन दिनों उनका पटना आना-जाना भी बेहद कम हो गया है, लिहाजा आपदा को अवसर में बदलने में सिद्धहस्त हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले संजय यादव तेजस्वी के नए सारथी के तौर पर अवतरित हुए हैं। तेजस्वी अभी बस उनकी सलाहों पर ही कान धर रहे हैं। मनोज झा के पिता भले ही अस्पताल में हों, पर तेजस्वी की आशावादी राजनीति को कम से कम वेंटिलेटर पर नहीं जाना चाहिए।

वसुंधरा के मन में क्या चल रहा है?

राजस्थान की महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया को बिसराना भाजपा के केंद्रीय शीर्ष के लिए आसान नहीं रहा, एक नए नवेले भाजपा सिरमौर को वहां की गद्दी सौंपने के बाद से राज्य में भगवा आशाओं का फलक किंचित धूमिल पड़ने लगा है। सो, पिछले दिनों बांसवाड़ा की एक रैली में पीएम मंच पर मौजूद तमाम नेताओं की अनदेखी करते सीधे वसुंधरा के पास जा पहुंचे और गर्मजोशी के साथ उनका खैर मकदम पूछा। इस घटना के बाद ही वसुंधरा के सुसप्राय: समर्थकों में एक नए जोश का उबाल आ गया। इसके बाद वसुंधरा की सर संघचालक मोहन भागवत से भी एक लंबी और सारगर्भित मुलाकात हुई। सो, राजस्थान में वसुंधरा की राजनीति ने नए कुलांचे भरने शुरू कर दिए। इस रामनवमी के मौके पर वसुंधरा ने अपने समर्थकों के लिए एक भोज रखा था, जिसमें बड़ी संख्या में वर्तमान और पूर्व विधायक भी जुटे। इस भोज में शामिल वसुंधरा के बेहद भरोसेमंद विधायक युनूस खान ने सुझाव रखा कि 'अब वक्त आ गया है कि मैडम पूरे राज्य का दौरा करें, हम जिलेवार इसका कार्यक्रम तय कर सकते हैं और इनके साथ कारों का एक बड़ा काफिला भी चलेगा।' इस पर वसुंधरा ने युनूस खान को रोकते हुए कहा-'नहीं, अभी इसका वक्त नहीं आया है। वैसे तो भगवान राम के जीवन में भी वनवास आया था। देखो मेरी उम्र 72 वर्ष की हो गई है, अब मुझे अपने लिए कुछ मांगना ठीक नहीं लगता, पर अगर मैं आप लोगों के लिए कुछ मांगूगी तो वह मिल सकता है।' माहौल थोड़ा संजीदा हो गया, इसे हल्का करने की नियत से वसुंधरा के एक करीबी विधायक श्रीचंद कृपलानी ने उनसे पूछा- 'मैडम, मंच पर पीएम आपसे क्या कह रहे थे?' वसुंधरा ने कहा, 'पीएम ने उनसे कहा-वसुंधरा जी हम-आप जैसे लोग किसी पद-प्रतिष्ठा से अब ऊपर उठ आए हैं।'

बूझो तो जाने, यह है कौन?

इन दिनों एक पुराना मामला जो 2006 का बताया जाता है, फिर से सुर्खियों की सवारी गांठ रहा है। पूरा सोशल मीडिया इसकी चर्चाओं से अटा पड़ा है। मोहन गुरुस्वामी का एक कथित पोस्ट 'एक्स' पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें बताया गया है कि कैसे केरल में हाईवे के 'पाटी-बेल' प्रोजेक्ट से जुड़े मलेशियाई इंजीनियर ने खुदकुशी कर ली थी। दरअसल, यह एक विश्व बैंक पोषित प्रोजेक्ट था जिसके अंतर्गत 1600 किलोमीटर के हाईवे का निर्माण होना था। इसी 'पाटी-बेल' परियोजना के प्रबंधक 58 वर्षीय ली सिन बेन ने 2006 के नवंबर में एक बड़े भ्रष्टाचार से पर्दा हटाते खुदकुशी कर ली थी। उस समय केरल में वाम मोर्चा की सरकार थी और तब शासन-प्रशासन पर ये आरोप लगे थे कि बिना रिश्वत लिए वे इस कंपनी के प्रोजेक्ट के पैसे रिलीज नहीं कर रहे थे। तब मामले की जद में राज्य के तत्कालीन पीडब्ल्यूडी सचिव आ गए थे। तत्कालीन केरल सरकार ने मामला प्रकाश में आते ही फौरन उनका तबादला अन्यत्र कर दिया। लगभग 19 सालों के बाद वही सचिव महोदय आज केंद्र सरकार के सबसे लाडले अधिकारी हैं और इन पर निष्पक्ष रहते लोकतंत्र के एक बड़े संचालन की जिम्मेदारी है। अब अगर आपने बिल्ली को खीर की रखवाली सौंप ही दी है तो इस मुल्क का ऊपर वाला ही रखवाला है।

योगी की नजर पूर्वांचली सांसदों पर

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब सियासी नेपथ्य की आहटों को पढ़ने में सिद्धहस्त हो गए हैं। पिछले दिनों योगी पूर्वांचल के आधा दर्जन से ज्यादा भाजपा सांसदों से मिले और उनके साथ अपने मन की बातें शेयर की। इस बैठक में शामिल होने वाले भाजपा सांसदों में दो राज्यसभा से आते हैं। ये दोनों सांसद थे नीरज शेखर और सीमा द्विवेदी। इसके अलावा इस बैठक में भाजपा के लोकसभा के 3-4 और सांसद मौजूद थे। योगी पहले भी पूर्वांचल के सांसदों की बैठक लेते रहे हैं, आमतौर पर ऐसी बैठकों के संयोजन का जिम्मा योगी अपने भरोसेमंद नेता रविन्द्र कुशवाहा को सौंपते रहे हैं। पर इस बार कुशवाहा सलेमपुर से लोकसभा का चुनाव हार गए थे। सो, उनकी जगह इस बैठक के संयोजन का काम किया बांसगांव के एक दलित सांसद कमलेश पासवान ने जो अभी केंद्र सरकार में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री भी हैं। इस दफे कमलेश को लोकसभा का चुनाव जितवाने के लिए योगी ने एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया था, बमुश्किल वह कमलेश को 3150 के मामूली वोटों के अंतर से ही जिता पाए थे। पर योगी को उस वक्त जोर का झटका लगा जब पासवान चुनाव जीतते ही दिल्ली जाकर भाजपा नेता जी की परिक्रमा करने लगे, क्योंकि उन्हें सरकार में मंत्री बनना था। वे मंत्री बन भी गए, योगी विरोध की अनुकंपा पाकर। फिर से अचानक उन्होंने पाला बदल लिया और लखनऊ आकर योगी की हाजिरी बजाने लगे हैं। यह बात दिल्ली को बेहद नागवार गुजरी, पल में तोला पल में माशा, उनके इस आचरण को भाजपा के नेता जी ने भी गंभीरता से लिया और एक दिन उन्हें उनके इसी आचरण के लिए कड़ी फटकार लगाई गई, यहां तक कह दिया गया कि 'आपके ऊपर भ्रष्टाचार के कई मुकदमें यहां तक कि जमीन हड़पने के मामले तक चल रहे थे, फिर भी हमने आपको मंत्री बनाया' ये मंत्री महोदय फूल-माला लेकर अपने दिल्ली वाले आका की परिक्रमा कर रहे हैं, पर अंदर ही अंदर उन्हें यह डर भी खाया जा रहा है कि 'कुछ भी हो मगर आने वाला वक्त तो योगी का ही है।'

राज्यसभा पाकर भी खुश नहीं गुप्ता जी

राजेंद्र गुप्ता पंजाब के एक बड़े कारोबारी हैं, जिन्हें इस बार आम आदमी पार्टी ने संजीव अरोड़ा द्वारा रिक्त की गई सीट से राज्यसभा में भेजा है। सूत्रों की मानें तो गुप्ता जी ने एक वक्त अकाली दल की भी काफी मदद की थी।

इस दफे जब पंजाब में विधानसभा चुनाव होने थे तो माना जाता है कि आप के दो बड़े नेता भगवंत मान और संदीप पाठक उनसे मिलने पहुंचे और उनसे आग्रह किया कि 'वे आम आदमी पार्टी की चुनावी मदद करें।' कहते हैं गुप्ता जी मान गए और इस चुनाव में उन्होंने दिल खोल कर आप की मदद की। जब आप चुनाव जीत गई तो इन्हीं नेताओं द्वारा कथित तौर पर गुप्ता जी से वायदा हुआ कि 'पार्टी आने वाले समय में उन्हें राज्यसभा में लेकर आएगी।'

सम्पादकीय...

डिजिटल युग

डिजिटल की दुनिया में अब ऐसा कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं बचा है जहां महिलाएं अपने सम्मान पर डाका डालने वाले साइबर खतरों से बचकर रह सकें। आज के दौर में दुनिया भर में 60 प्रतिशत से अधिक युवतियां और महिलाएं सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर उत्पीड़न का सामना कर रही हैं। भारत इस समय युवाओं का देश है। यहां की युवा आबादी ऑनलाइन दुनिया में सबसे ज्यादा सक्रिय है। इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाली महिलाओं की बढ़ती संख्या एक सकारात्मक बदलाव है लेकिन इसने महिलाओं को वर्चुअल दुनिया में खतरों के जोखिम में डाल दिया है। भारत के प्रधान न्यायाधीश बी.आर. गवई ने डिजिटल युग में महिलाओं की सुरक्षा के खतरे को रेखांकित करते हुए कहा है कि डिजिटल दौर में बालिकाओं की सुरक्षा मुख्य प्राथमिकता होनी चाहिए। यह सुनिश्चित होना चाहिए कि तकनीकी प्रगति के साथ-साथ नैतिक सुरक्षा भी हो। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। लड़कियों को होने वाले खतरे सिर्फ भौतिक स्थानों तक सीमित नहीं हैं। अब यह डिजिटल दुनिया में विस्तार पा चुके हैं। ऑनलाइन उत्पीड़न, साइबर बुलिंग, डिजिटल स्टाकिंग, व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग और डीप फेक इमेजनरी तक चुनौतियां बढ़ी हैं। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने मुंबई में आयोजित 'साइबर सुरक्षा जागरूकता माह' के उद्घाटन समारोह में उनकी बेटी के साथ ऑनलाइन गेमिंग के दौरान हुई एक घटना का जिक्र किया। अभिनेता ने बताया कि ऑनलाइन गेम खेलते वक्त उनकी 13 साल की बेटी से न्यूड तस्वीरें मांगी गई। उन्होंने आने वाली पीढ़ी को साइबर अपराध के बढ़ते खतरों से सुरक्षित रखने के लिए महाराष्ट्र सरकार से स्कूलों में साप्ताहिक साइबर पीरियड शुरू करने का आग्रह भी किया। यह घटना न केवल साइबर अपराध की गंभीरता को रेखांकित करती है, बल्कि हर माता-पिता के लिए सबक बन गई है। इसके अलावा अभिनेत्री रश्मिका मंदाना, ऐश्वर्या राय और कई अभिनेता भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर डीप फेक तस्वीरों को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटा चुके हैं। आए दिन साइबर अपराधों से जुड़े मामले अदालतों में पहुंच रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार वर्ष 2024 में महिलाओं द्वारा दर्ज कराए गए साइबर अपराधों की संख्या लगभग 48500 थी, जो वर्ष 2020 में दर्ज लगभग 22000 मामलों से दोगुनी है। अप्रैल 2025 में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, 50 प्रतिशत से अधिक महिला इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने किसी न किसी रूप में ऑनलाइन उत्पीड़न का अनुभव किया है। इनमें बदनाम करने के उद्देश्य से मॉर्फ की गई तस्वीरें वायरल करना, धमकी भरे संदेश भेजना और निजी जानकारी के आधार पर ब्लैकमेल करने जैसे अपराध शामिल हैं। वर्ष 2025 में सामने आए कुछ प्रमुख मामले साइबर अपराधों की गंभीरता को उजागर करते हैं। पुणे में एक 64 वर्षीय महिला वैज्ञानिक को डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लगभग पौने दो करोड़ रुपए से अधिक की ठगी का शिकार बनाया गया। गुजरात में एक बड़े साइबर अपराध रैकेट का भंडाफोड़ हुआ, जहां महिलाओं को व्हाट्सएप कॉल्स के जरिए डराया और धमकाया गया। एक अन्य मामला पुणे की महिला का था जिसने ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग घोटाले में लगभग तेरह लाख रुपए गंवा दिए। इन अपराधों का न केवल वित्तीय, बल्कि मानसिक प्रभाव भी गंभीर होता है। ऐसे अनेकों मामले पूरे देश में देखने को मिले हैं, जिसमें विशेष तौर से महिलाओं को साइबर ठगों द्वारा शिकार बनाया गया है। महिलाएं अवसाद, तनाव और सामाजिक अलगाव का शिकार हो जाती हैं। दुर्भाग्यवश, समाज में साइबर पीड़ितों को दोषी ठहराने की प्रवृत्ति के कारण कई महिलाएं शिकायत दर्ज कराने से हिचकती हैं, जिससे अपराधी आसानी से बच निकलते हैं। हालांकि भारत सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन उनकी प्रभावशीलता पर सवाल उठते हैं। वैसे तो देश में साइबर अपराध के लिए सूचना प्रौद्योगिकी नियम (आईटीएक्ट 2000) में हैकिंग, इंटरनेट पर अश्लील सामग्री का प्रसार, प्राइवेसी का उल्लंघन, धोखाधड़ी के उद्देश्य से प्रकाशन इत्यादि को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है लेकिन इसमें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विशिष्ट रूप से कोई उल्लेख नहीं है। लड़कियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी ढांचे को मजबूत करना होगा और इसके लिए विशेष कानून बनाने होंगे। सीजेआई बी.आर. गवई ने भी लड़कियों के अधिकारों की रक्षा के लिए डिजिटल गवर्नेंस पर बल दिया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि हमें लड़कियों को शिक्षित करने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने का काम भी करना होगा। लड़कियों की रक्षा करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। अभिभावकों को भी चाहिए कि अपने बच्चों को पूरी जानकारी दें और उन्हें लगातार सतर्क करते रहें।

स्कूलों में भी इस विषय को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, ताकि बच्चे खुद को बचाएं। आर्टिफिशियल इंटेलीजेंसी ने डिजिटल युग को और भी खतरनाक बना दिया है। हालांकि कई क्षेत्रों में एआई वरदान सिद्ध हो रही है। बेहतर यही होगा कि घर का वातावरण ऐसा बनाएं कि बच्चे अभिभावकों से डरने की बजाय ऑनलाइन खतरों के बारे में उनसे बात कर सकें। ई-मेल और व्हाट्सएप पर आने वाले किसी भी लिंक के जरिये गेम्स या अन्य सामग्री डाउनलोड करने से बचें और अनजान लोगों से चैटिंग न करें। अगर कोई उन्हें डराये, धमकाए या ब्लैकमेलिंग का प्रयास करे तो तुरन्त पुलिस के साइबर अपराध सेल में शिकायत करें। ऐसे मामलों को सतर्कता और संवेदनशीलता से ही सम्भाला जा सकता है। केन्द्र सरकार को भी नए कानून बनाकर डिजिटल वातावरण को सुरक्षित बनाना होगा।

धौंस-धमकान की नीति ट्रंप के लिए होगी आत्मघाती

धमकाने और धौंस की नीति पर चल रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी झूठी चौधराहट और खनिजों के चक्कर में लगता है दुनिया के देशों में अमेरिकी विरोधियों की बड़ी फौज ही तैयार करते जा रहे हैं। शांति के नोबल पुरस्कार का ट्रंप का सपना धरा का धरा ही रह गया है और अब 30 प्रतिशत टैरिफ के अतिरिक्त 100 प्रतिशत और यानी कि 130 प्रतिशत टैरिफ लगाकर चीन के खिलाफ भी आर्थिक क्षेत्र में खुली जंग ही छेड़ दी है। कनाडा को अमेरिका का नया राज्य बनाने और रूस यूक्रेन युद्ध के पीछे के अमेरिकी एजेंडे को आज दुनिया के देश समझ ही चुके हैं। पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष के साथ डिनर के माध्यम से अमेरिका के गिरते स्तर को दुनिया के देश देख ही चुके हैं। भारत जैसे देश से पंगा लेना सबके सामने है। पाकिस्तान पर भी खनिजों के चक्कर में डोरे डाले जा रहे हैं। देखा जाए तो ट्रंप का रवैया जिस तरह का दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद देखने को मिल रहा है वह गली मौहल्ले के गुंडे मवाली जैसा ही दिखाई देने लगा है। दुनिया के देशों को धमकाना जैसे ट्रंप का काम ही हो गया है। दुनिया के देशों में युद्ध समाप्त कराने का झूठा तमगा पहनने के प्रयास और शांति के नोबल पुरस्कार के लिए नोबल संस्था तक को धमकाने के कुत्सित प्रयास से ट्रंप स्वयं और अमेरिका दोनों की ही हेठी कराने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। चीन से पहले भारत पर भी 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने और वीजा नियमों में बदलाव से अपने ही पांवों में ठोकर मारी है। हालांकि भारत किसी भी तरह के ट्रंप के दबाव में नहीं आया और सबसे बड़ी तोहिन तो यह रही कि भारत ने इस पर प्रतिक्रिया तक व्यक्त करने की जेहमत नहीं उठाई जिसके कारण अमेरिका का तमतमाना लाजिमी भी हो जाता है। अमेरिका ने भारत पर सौ प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद सोचा था कि भारत घुटनों के बल आ जाएगा पर हुआ इसका उल्टा ही और भारत ने नये बाजार की संभावनाएं तलाशना आरंभ कर दिया। आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि अब चीन पर अमेरिकी टैरिफ वार का लगता है भारत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और भारत की निर्यात की संभावनाओं को पर लगने के अधिक आसार हो जाएंगे। स्वाभाविक है चीन के उत्पाद महंगे हो जाएंगे और भारतीय उत्पाद कपड़ा, हेण्डिक्राफ्ट, खिलौने आदि आदि तुलनात्मक रुप से सस्ते होंगे तो भारतीय उत्पादों की मांग कम होने के स्थान पर बढ़ेगी ही। जानकारों का मानना है कि अमेरिकी टैरिफ वार अमेरिका पर ही उल्टा पड़ना है।

आज अमेरिका भारतीय प्रतिभाओं का लाभ उठा रहा है पर नए वीजा नियमों और विदेशियों को पलायन करने के बाध्यकारी आदेशों से अमेरिका आने वाले समय में शून्यता की ओर ही बढ़ेगा। लगता तो यहां तक है कि आने वाले समय में अमेरिका विदेशी प्रतिभाओं से शून्य हो जाएगा और अमेरिकी प्रतिभाओं को आगे आना इतना आसान भी नहीं होगा। इधर ट्रंप के व्यवहार के चलते श्वेत-अश्वेत की खाई चौड़ी होती जा रही है। बीसवीं सदी के अंत में दुनिया के देशों में विश्वग्राम का सपना देखा था, इस दिशा में दुनिया के देश आगे भी बढ़े थे और फिर संचार क्रान्ति ने तो दुनिया के देशों को लगभग विश्वग्राम बना ही दिया पर जिस तरह के हालात ट्रंप जैसे अति महत्वाकांक्षी द्वारा उठाये जा रहे हैं, उससे विश्वग्राम का सपना बीच राह में ही टूटता नजर आने लगा है। एक दूसरे के सहयोग और समन्वय की बात तो ट्रंप ने भुला ही दी है। फिर सबको एक ही लकड़ी से हांकने की नीति भी आत्मघाती बनती जा रही है। अमेरिका को समझना यह होगा कि आज आप किसी पर टैरिफ का दबाव बढ़ाते हो तो अन्य देशों के लिए राह आसान कर रहे हो। हो यह रहा है कि टैरिफ की मार का सबसे नकारात्मक प्रभाव अमेरिका पर ही पड़ना है। एक तरफ अमेरिका को जरुरतों को पूरा करने में जुटे विदेशी देशों के उत्पाद महंगे होंगे तो दूसरी और अमेरिकी इकोनोमी पर भी निश्चित रुप से विपरीत प्रभाव पड़ना ही है। आज दूसरे देशों के प्रति निर्भरता बढ़ी है और ऐसे में आगे बढ़ने के लिए दो मोर्चों पर जुटना पड़ता है। पहले तो यह कि दूसरे देशों में आ रहे बदलावों, तकनीक आदि को समझना और फिर उस तकनीक को अपनी जरुरत के अनुसार अपने देश में विकसित करना। अमेरिका दरअसल दूसरों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करना चाहता है पर वह यह भूल रहा है कि इकोनोमी एक दूसरे की सहायता से आगे बढ़ती है। देसी-विदेशी मांग को बढ़ाना ही होता है। स्थानीय के साथ ही विदेशों में भी बाजार खोजना होता है। ऐसे में बड़े बड़े व्यापार समझौते देशों के बीच होते हैं। अमेरिका ने जिस तरह से व्यापार समझौतों को दरकिनार कर टैरिफ वार और तरह तरह के अवरोध खड़े करने के प्रयास किये हैं उनका असर अंततोगत्वा अमेरिकी इकोनोमी पर भी पड़ना ही है। लगता है ट्रंप अमेरिका को आत्मघाती गोल की तरफ ले जा रहा है। दुनिया के देशों को वैश्विक ग्राम की परिकल्पना को ही आगे बढ़ाना होगा।

करोड़पति हैं अनेक भारतीय लेखक

एक अच्छा लेखक जब 'रायल्टी' के आधार पर चर्चा में आता है तो लेखन की दुनिया का सम्मान बढ़ जाता है। प्रख्यात हिंदी कवि विनोद कुमार शुक्ल को हाल ही में उनकी एक कृति 'दीवार में एक खिड़की रहती थी' के लिए 30 लाख की 'रायल्टी' (मानदेय) मिली है। अब उनका नाम भारतीय पाठकों के लिए आकर्षण का बिन्दु बन गया है। वे पाठक जो अब तक उनकी काव्य-प्रतिभा के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, अब उनकी इस कृति को खरीद कर चाव से पढ़ने लगे हैं।'रायल्टी' के बारे में चर्चाएं छिड़ी हैं तो अब चेतन भगत का नाम भी पहली कतार में उभर आया है। आज से छह वर्ष पूर्व 2019 में उनकी कुल 'रायल्टी' 28 करोड़ रुपए थी जबकि जासूसी उपन्यास लेखक को हर छमाही में 30 लाख रुपए रायल्टी के रूप में मिलने की चर्चा है। ऐसे नामों में इब्ने सफी, दत्तभारतीय आदि हैं। करोड़ों की 'रायल्टी' पाने वाले भारतीय लेखकों में विक्रम सेठ भी हैं, जिनके बारे में यह भी चर्चा है कि उन्हें उनकी किसी भी आगामी कृति के लिए अग्रिम 'रायल्टी' मिल जाती है। इसी क्रम में अन्य चर्चित लेखकों के नाम हैं सलमान रुश्दी, रस्किन बांड, झुम्पा लाहिड़ी, आरके नारायण, अनीता देसाई। इनके अलावा पुरानी पीढ़ी के करोड़ों की रायल्टी पाने वाले नामों से गुरुदेव टैगोर, मुंशी प्रेमचंद, खुशवंत सिंह, अमृता प्रीतम, श्री लाल शुक्ल, यशपाल, विमल मित्र, कृष्णा सोबती, धर्मवीर भारती, महादेव वर्मा, निराला, वृंदावन लाल वर्मा, अज्ञेय आदि के नाम हैं। इनमें ऐसे नाम भी हैं जिन्हें फिल्म जगत से भी उनकी कृतियों के लिए करोड़ों की राशि मिली। एक केंद्रीय अधिसूचना के तहत गुरुदेव टैगोर की कृतियों से होने वाली आज शांति निकेतन को अदा होती है, मगर अपने जीवनकाल में इनमें से अनेक ऐसे लेखक थे, जिनकी जीवन यात्रा विफलता एवं तंगहाली में बीती। ऐसे प्रतिष्ठित लेखकों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी शामिल थे और अपने शुरुआती दौर में मुंशी प्रेमचंद भी शामिल थे। भारतीय उपमहाद्वीप के सर्वाधिक चर्चित लेखक मंटो को कुछ रुपयों के बदले में अपनी एक बहुचर्चित पुस्तक की पांडुलिपि के सर्वाधिकार भी बेचने पड़े थे। हबीब जालिब की पूरी जिंदगी तंगहाली में गुजरी। उनकी बेटी अब भी सस्ते अस्पतालों में अपनी बीमारियों का इलाज कराने को मोहताज है। वैसे साहिर लुधियानवी को भी अपने लोकप्रिय काव्य-संकलनों से नाममात्र के पैसे ही मिले थे। उन्हें जो भी मिला, फिल्मी-गीतों से मिला। साहिर बताते थे, उनके काव्य संकलन 'तल्खियां' के पाकिस्तान में ही 16 संस्करण छपते थे, मगर उन्हें वहां के प्रकाशकों ने एक रुपया भी नहीं दिया। गैर-साहित्यिक रूमानी हिंदी लेखकों गुलशन नंदा, दत्त भारती, कुशवाहा कांत आदि शामिल थे। हिंदी में निरंतर लेखन का कीर्तिमान आचार्य चतुरसेन शास्त्री व वैद्य गुरुदत्त ने स्थापित किया था। इधर, पौराणिक आख्यानों पर हिंदी व अंग्रेजी में लेखन की एक लहर चल निकली है देवदत्त पटनायक, आशीष नंदी, अमित त्रिपाठी आदि ने लेखन, प्रकाशन व 'रायल्टी' के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। ये लेखक हिंदी व अंग्रेजी में समान रूप से लोकप्रिय रहे हैं। भारतेन्दु-युग में एक विशेष उल्लेखनीय बात यह भी थी, लाखों पाठकों ने देवकीनंदन खत्री के उपन्यास पढ़ने के लिए ही हिंदी सीखी थी।

सोनम वांगचुक को तो जेल जाना ही था!

डॉ. द्रोण कुमार शर्मा

सरकार जी ने अभी बीस एक दिन पहले एक 'देशद्रोही', 'दुर्दान्त आतंकवादी' को गिरफ्तार किया है। और लेह से गिरफ्तार कर के उसे जोधपुर की जेल में सड़ने के लिए डाल दिया। उसका नाम सोनम वांगचुक है। मुझे तो उसके नाम से ही समझ आता है कि वह कोई देशद्रोही ही है, आतंकवादी ही है। ऐसा 'चीनियों' जैसा नाम किसी ऐसे आतंकवादी का ही हो सकता है जिसका चीन से संबंध हो। ऐसा चीनियों जैसा नाम किसी देशद्रोही का ही हो सकता है। वह अपना नाम कोई सुरेंदर, योगेंदर, नरेंदर जैसा नहीं रख सकता था क्या? या फिर अमित, अजीत, अजय जैसा कुछ। नाम कोई भी हो, अपने नाम के आगे पीछे योगी, साधु, संत या बाबा लगा कर भी तो देशभक्त बना जा सकता है। चलो नाम की बात छोड़ो, काम की बात करते हैं। भई नाम तो मां बाप ने रख दिया। पर काम तो आपने तो अपने आप चुना। ये सोनम वांगचुक भाईसाब कर क्या रहे हैं? पता चला है इंजीनिरिंग पढ़ी थी। इंजीनियरिंग पढ़ी थी तो देश के उत्थान में लगते। ऐसे पुल बनाते जो बनते ही टूट जाते। ऐसी सड़कें बनाते जो उद्घाटन का नारियल फोड़ते ही क्रेक कर जातीं। पहली बारिश में सारी बह जातीं। देश के लिए किसी कंस्ट्रक्टिव काम में लगते, यह क्या ही डिस्ट्रक्शन में लग गए। कर क्या रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आज कल के काल में पढ़ाना तो वैसे भी देशद्रोह है। यह पढ़ना लिखाना जुर्म है आज कल। और सोनम वांगचुक पढ़ा भी किनको रहे हो, गरीब बच्चों को। ऐसे बच्चों को जो फेल हो गए हों। यह तो बहुत ही बड़ा देशद्रोह है। अरे भाई, देशप्रेमी हो और स्कूल खोलना ही है तो कोई ऐसा स्कूल खोलो जिसमें लाखों की फीस हो और अमीरों के बच्चे पढ़ते हों। ऐसे देशप्रेमी देश भर में लाखों की संख्या में फैले हुए हैं और धड़ल्ले से स्कूल चला रहे हैं। लेकिन सोनम वांगचुक जैसे देशद्रोही, जो गरीब बच्चों को पढ़ाएं, और वे बच्चे पढ़ लिख कर सरकार जी से नौकरी मांगें, बेरोजगारी बढ़ाएं, यह सरकार जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। यह सरकार जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कहते हैं यह सोनम वांगचुक एक वैज्ञानिक भी है। विज्ञान के मामले में कई खोज भी की हैं। बताओ जरा, सोनम

वांगचुक ने भला ऐसा कोई बादल बनाया है जो रडार के सामने आ जावे तो रडार हवाई जहाज को न देख सके। या फिर ऐसी रडार जो बादलों के पार न देख सके। नहीं ना। या फिर नाले की गैस से खाना बनाने की विधि खोजी हो। ए प्लस बी होल स्क्वायर में से एक्स्ट्रा टू ए बी निकाला है? और उसका इस्तेमाल भी किया हो। या फिर...। बताओ ऐसा क्या किया है उसने कि सरकार जी उसको वैज्ञानिक मानें। अरे छोड़ो यार, दो चार छोटी मोटी खोज कर दी होंगी और अपने को वैज्ञानिक समझ बैठे हैं। ऐसे वैज्ञानिकों को तो हमारे सरकार जी जूती पर रखते हैं। समझे क्या? यह देशद्रोही पाकिस्तान भी हो आया। यू एन की मीटिंग के लिए गया था। और वह मीटिंग थी पर्यावरण पर। पर्यावरण से ध्यान आया, हमारे तो सरकार जी कब का बता चुके हैं, पूरे देश को बता चुके हैं, यह पर्यावरण वर्यावरण कुछ नहीं होता है। वह तो हम बूढ़े हो रहे हैं इसलिए सर्दी गर्मी ज्यादा लगती है। इस सोनम वांगचुक ने वहां जा कर सरकार जी की थ्योरी का समर्थन तो नहीं ही किया होगा। हो गई ना देशद्रोह की बात। वहां जा कर पर्यावरण की धज्जियां उधेड़ता और सरकार जी की बात को रखता तो होती देशप्रेम की बात। असलियत में पर्यावरण तो बहाना था। असली मकसद तो पाकिस्तान जाना था। अरे पाकिस्तान जाना है तो यू एन के आमंत्रण की क्या जरूरत है। बिना निमंत्रण के नहीं जा सकते थे क्या? बिना निमंत्रण जाते और बिरयानी खा कर आ जाते। उससे आपकी देशभक्ति भी बनी रहती है और पूरा आई टी सेल आपकी प्रशंसा करता। देशभक्ति बचाने के लिए एक और चीज है। अगर पाकिस्तान जाओ तो जिन्ना की मजार पर फूल चढ़ा कर आओ, सिर नवा कर आओ। एक बात और, हमें वह वीडियो या फोटो भी ढूंढनी है कि कहीं ये सोनम वांगचुक पाकिस्तान में किसी पाकिस्तानी से हाथ तो नहीं मिला रहे। हम पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ खेल तो सकते हैं, उनके बल्ले से निकला हुआ कैच तो पकड़ सकते हैं, उनके द्वारा फेंकी गई गेंद पर चौका, छक्का तो मार सकते हैं। पर हाथ नहीं मिला सकते हैं। साथ साथ खेलना कूदना देशप्रेम है और हाथ मिलाना देशद्रोह। यह देश का न्यू नॉर्मल है। सोनम वांगचुक बांग्लादेश के मोहम्मद युनुस जी से भी मिला। कई साल पहले मिला। ये मोहम्मद युनुस वही हैं जिन्होंने बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद वहां की सत्ता सम्हाली थी। दोनों, सोनम वांगचुक और मोहम्मद युनुस ने क्या बातचीत की होगी? यही ना कि तख्तापलट कैसे करना है और उसके बाद सत्ता की बागडोर कैसे सम्हालनी है। और कोई बातचीत तो ये दोनों कुछ कर ही नहीं सकते थे। और मिले भी कब, 2020 में। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन से चार साल पहले। न जाने कब से खिचड़ी पका रहे थे ये दोनों। लेकिन हमारे देश के सरकार जी के दिमाग में एक ही बात समाती है कि दो दो बुद्धिजीवी मिलेंगे तो उनकी सत्ता परिवर्तन की बात ही करेंगे। जिसके दिमाग में चौबीस घंटे सत्ता ही घूमती रहती है, वह और कोई बात सोच ही कैसे सकता है। इल्जाम तो यह भी है कि सोनम वांगचुक हमारे देश की सेना को भी पटा रहे हैं। सेना को लेह लद्दाख के ठंडे बर्फीले मौसम में रहने के लिए सोलर पावर से गर्म रहने वाले टेंट बना रहे थे। वह भी अपने पैसे से। यह तो पक्का देशद्रोह का काम था। पहले आप अपना प्रपोजल सरकार को भेजते। सरकार को अच्छा लगता तो वह प्रपोजल पर विचार करने के, उसको पास करने की रिश्वत मांगती। फाइल विभिन्न मंत्रालयों में जाती, सबकी फीस लगती। ले दे कर सरकार प्रपोजल पास करती। सरकार पास करती और हमारे अडानी जी बनाते। यह होता है देशप्रेम। सबको अपना हिस्सा मिलता। जो लोग शहीद सैनिकों के ताबूत में कमीशन खा गए, वो इसमें नहीं खाते। सोनम वांगचुक बहुत बड़े देशद्रोही हैं। जो देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। पहले तो चीनियों जैसा नाम रखा, फिर बच्चों के लिए स्कूल खोले। वैज्ञानिक खोजें कीं। पर्यावरण पर काम किया। पाकिस्तान गए। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युसूफ से मिले। और सैनिकों के लिए अपने पैसे से सोलर ऊर्जा से गर्म रहने वाले आवास बनवाये। इतना ज्यादा देशप्रेम में कोई करता है। जरूर ही देशद्रोह में किया होगा। सरकार जी ने अच्छा ही किया। सोनम वांगचुक को देशद्रोह और आतंकवाद की ऐसी धाराओं में गिरफ्तार किया है कि अब सारी जिंदगी जेल में ही गुजरेगी। बच्चू स्कूल चलाना, पर्यावरण, वैज्ञानिक खोज, विश्व प्रसिद्ध लोगों से मिलना, सैनिकों के लिए सुविधाएं बनाना, सब भूल जायेगा जब लेह जैसे ठंडे इलाके में रहने वाले सोनम वांगचुक की बाकी जिंदगी जोधपुर जैसे गर्म इलाके की जेल में गुजरेगी। हां, सबक सिखाने के लिए सरकार जी को एक काम और करना चाहिए। जेल की सेल में हीटर और लगवा देने चाहियें। और सरकार जी उसका ऐसा उत्पीड़न करना कि आगे आने वाली पीढ़ियां भी याद रखें। आपके उत्पीड़न की कहानियां भी देश वैसे ही सुनाये जैसे अंग्रेजों के उत्पीड़न की सुनाई जाती है। सचमुच, सरकार जी हैं तो सब मुमकिन है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार पाठी ने करना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, सराय पीपलथला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार पाठी, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/0882)

हर घर स्वदेशी अभियान को बल देकर आत्मनिर्भर बनेगा भारत - पी.एन पाठक

कसया, कुशीनगर।

विधायक ने सामुदायिक भवन का किया लोकार्पण - 12.50 लाख की लागत से नवनिर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण कर जनता को किया समर्पित

सोमवार को कुशीनगर विधायक पी.एन पाठक ने ग्रामसभा अंध्या के दुर्गा मंदिर (ललका बाबा स्थान) के समीप विधायक निधि से निर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। विधायक श्री पाठक ने 12.5 लाख की लागत से निर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया। इस दौरान विधायक श्री पाठक ने विधि-विधान से पूजन किया और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच शिलापट्ट का लोकार्पण कर पूजन-अर्चन किया।स्थानीय लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका माल्यार्पण किया और बुके देकर स्वागत किया।विधायक श्री पाठक ने कहा कि भाजपा सरकार में चौतरफा विकास हो रहा है, क्षेत्र का चातुर्दिक विकास उनकी प्राथमिकता है। हर घर स्वदेशी अभियान को बल देकर भारत आत्मनिर्भर बनेगा। हर घर स्वदेशी घर घर स्वदेशी अभियान को अपनाने का आह्वान किया। इस दौरान वीरेन्द्र मिश्र, कस्तूर जायसवाल, धर्मेंद्र यादव, प्रधान प्रेम गौड़, रामलोचन शर्मा, शिदेश्वर शाही, रजनीश मिश्रा, बैजू पटेल, सर्वेश गुप्ता,अवर अभियंता पी.एन मिश्रा, अमरजीत कुशवाहा, राज पाठक, सिब्लू सिंह ,सभासद सूर्यनाथ यादव, राकेश यादव सहित लोग मौजूद रहे।

डीआईजी शिवशिम्पी चन्नप्पा ने देवरिया में चलाया मिशन शक्ति जागरूकता अभियान, महिलाओं को बताया सुरक्षा के अधिकार

देवरिया।

महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के उद्देश्य से चलाए जा रहे मिशन शक्ति फेज15.0 अभियान के तहत सोमवार को डीआईजी गोरखपुर परिक्षेत्र, शिवशिम्पी चन्नप्पा ने जनपद में पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के साथ थाना बनकटा और थाना सलेमपुर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने न केवल पुलिस व्यवस्था की गहन समीक्षा की, बल्कि महिला सशक्तिकरण के प्रति समाज को प्रेरित करने वाला सशक्त संदेश भी दिया।

बनकटा थाने पर विशेष चौपाल का आयोजन

डीआईजी शिवशिम्पी चन्नप्पा और एसपी संजीव सुमन ने थाना बनकटा पर मिशन शक्ति विशेष चौपाल का आयोजन किया। चौपाल में मौजूद महिलाओं, छात्राओं और ग्रामीण महिलाओं को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं, हेल्पलाइन सेवाओं और उनके कानूनी अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। डीआईजी ने कहा कि मिशन शक्ति का उद्देश्य केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त नागरिक के रूप में स्थापित करना है। उन्होंने छात्राओं को 1090 (महिला हेल्पलाइन), 112 (आपातकालीन सेवा), 181 (महिला सहायता), 1076 (मुख्यमंत्री हेल्पलाइन) और 1930

सलेमपुर और बनकटा थाने का निरीक्षण कर डीआईजी ने दिए सख्त निर्देश

(साइबर ठगी शिकायत) जैसे नंबरों की जानकारी दी और किसी भी उत्पीड़न या संकट की स्थिति में तुरंत पुलिस या हेल्पलाइन से संपर्क करने की सलाह दी। साथ ही, बढ़ते साइबर अपराधों के खतरे को लेकर सतर्क रहने और संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधियों की सूचना तुरंत देने का आग्रह किया। निरीक्षण के दौरान डीआईजी ने थाना कार्यालय के अभिलेखों अपराध रजिस्टर, भूमि विवाद रजिस्टर, बीट सूचना रजिस्टर, आगंतुक पंजी, हत्या/बलवा रजिस्टर आदि का गहन अवलोकन किया और उन्हें नियमित रूप से अद्यतन करने के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने मिशन शक्ति केंद्र का भी निरीक्षण कर उसके रजिस्टरों की समीक्षा की और कमियों को सुधारने के निर्देश दिए।

सलेमपुर थाने पर औचक निरीक्षण और संवाद कार्यक्रम

इसके बाद डीआईजी शिवशिम्पी चन्नप्पा ने थाना सलेमपुर का औचक निरीक्षण किया, जहां उनके साथ पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन, अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी सुनील कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी सलेमपुर मनोज कुमार, प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार पटेल सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाना परिसर की स्वच्छता, अभिलेखों के रखरखाव, मालखाना, कंप्यूटर कक्ष, महिला हेल्पडेस्क, आगंतुक पंजी और लॉकअप की स्थिति का गहन परीक्षण किया। उन्होंने थाने में लंबित विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण और अभिलेखों के संधारण में पारदर्शिता लाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के उपरांत डीआईजी ने थाना परिसर में उपस्थित महिलाओं, बालिकाओं और छात्राओं के साथ संवाद किया। इस संवाद में उन्होंने मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन से जुड़ी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस का उद्देश्य केवल अपराध रोकना नहीं, बल्कि महिलाओं में सुरक्षा और आत्मविश्वास की भावना को मजबूत करना भी है। कार्यक्रम में महिला पुलिसकर्मियों ने आत्मरक्षा तकनीकों का प्रदर्शन कर छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए। डीआईजी ने कहा कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है, और मिशन शक्ति का यही मूल लक्ष्य है सुरक्षित नारी, सशक्त नारी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन ने भी छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की छेड़खानी या उत्पीड़न की स्थिति में एंटी रोमियो स्क्वॉड और पुलिस हमेशा तत्पर है। उन्होंने बताया कि एंटी रोमियो स्क्वॉड नियमित रूप से विद्यालयों, कॉलेजों और बाजारों में गश्त कर रहा है, ताकि महिलाओं को सुरक्षित माहौल मिल सके। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी सुनील कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी भाटपार रानी दीपशिखा वर्मा, प्रभारी निरीक्षक बनकटा, इंस्पेक्टर सलेमपुर सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

चिकित्सकों को सिखाए गए सर्पदंश उपचार के आधुनिक तरीके

देवरिया।

सर्पदंश न्यूनीकरण पर 63 चिकित्सकों को प्रशिक्षण

जिले में सर्पदंश के बढ़ते मामलों पर प्रभावी नियंत्रण और त्वरित उपचार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सोमवार को मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय स्थित धनवंतरि सभागार में एक दिवसीय सर्पदंश न्यूनीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम राहत आयुक्त कार्यालय और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में, जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के कुशल मार्गदर्शन एवं निर्देशन में संपन्न हुआ। प्रशिक्षण में जनपद के 63 चिकित्सकों सहित आपातकालीन वार्डों में कार्यरत डॉक्टरों को सर्पदंश के चिकित्सीय प्रबंधन, आपातकालीन प्रतिक्रिया, और सामुदायिक संचार से संबंधित वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक जानकारी दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) रामशंकर और मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. ए.के. गुप्ता ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर राहत आयुक्त भानु

चन्द्र गोस्वामी ने कहा कि सर्पदंश ग्रामीण क्षेत्रों में मृत्यु का एक प्रमुख कारण है, इसलिए चिकित्सकों को सही दिशा में प्रशिक्षित करना आवश्यक है ताकि वे समय रहते प्रभावी उपचार कर सकें। प्रशिक्षण सत्र का संचालन राज्यस्तरीय मास्टर ट्रेनर डॉ. अनिरुद्ध कुमार गुप्ता, डॉ. विजय कुमार, डॉ. अनिल कुमार सिंह, डॉ. तारकेश्वर नाथ वर्मा और डॉ. अजीत कुमार गुप्ता ने किया। उन्होंने पावर प्वॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से सर्पदंश के क्लिनिकल मैनेजमेंट, सपोर्टिव केयर और एंटी-स्नेक वेनम थेरेपी की प्रक्रिया पर विस्तार से जानकारी दी। विशेषज्ञों ने बताया कि सर्पदंश की स्थिति में प्रारंभिक निर्णय और त्वरित उपचार ही मरीज की जान बचाने की कुंजी है। प्रशिक्षण में भाग लेने वाले सभी चिकित्सकों को 'स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन' पुस्तिका भी प्रदान की गई ताकि वे उपचार के मानक प्रोटोकॉल का पालन कर सकें। कार्यक्रम का संचालन आपदा विशेषज्ञ पंकज कुमार ने किया। इसे सफल बनाने में विशेष कार्यकारी अधिकारी रंजन पांडेय, डॉ. अश्विनी कुमार पांडेय, विकास कुशवाहा और पंकज कुमार पांडेय का विशेष योगदान रहा।

आंगनबाड़ी केंद्रों पर सामग्रियों का वितरण 15 व 16 अक्टूबर को

कुशीनगर। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया है कि जनपद के अन्तर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर लाभार्थियों को वितरण हेतु सामग्री प्राप्त हो चुकी है। यह सामग्री माह-जुलाई 2025 के आपूर्ति आदेश के अनुसार है। मुख्य विकास अधिकारी, कुशीनगर के निर्देशानुसार जनपद के हाटा एवं (नगरीय माह जुलाई,अगस्त, सितंबर एवं ग्रामीण जुलाई 2025) के परियोजनाओं के आंगनबाड़ी केन्द्रों से उपरोक्त सामग्री का वितरण दिनांक 15 व 16 अक्टूबर 2025 को किया जायेगा। उक्त दिवस को संबंधित परियोजनाओं के सी0डी0पी0ओ0 व मुख्य सेविका भ्रमणशील रहेगें और कम से कम 05 केन्द्रों का भ्रमण करेंगें। उन्होने बताया कि 6 माह से 03 वर्ष के बच्चे को गेहूँ दलिया प्रति माह 1 कि0 ग्रा0, फोर्टीफाइड राइस प्रति माह 1 कि0 ग्रा0 व चना दाल प्रति माह 1 कि0 ग्रा0 और खाद्य तेल प्रति माह 455 मिलीलीटर। 03 वर्ष से 06 वर्ष के बच्चे को गेहूँ दलिया प्रति माह 500 ग्रा0, फोर्टीफाइड राइस प्रति माह 500 ग्रा0 व चना दाल प्रति माह 500 ग्रा0। गर्भवती एवं धात्री महिलाओ को गेहूँ दलिया प्रति माह 1.5 कि0 ग्रा0, फोर्टीफाइड राइस प्रति माह 1.5 कि0 ग्रा0 व चना दाल प्रति माह 1.5 कि0 ग्रा0 और खाद्य तेल प्रति माह 455 मिलीलीटर। अति कुपोषित बच्चे को गेहूँ दलिया प्रति माह 1.5 कि0 ग्रा0, फोर्टीफाइड राइस प्रति माह 1.5 कि0 ग्रा0 व चना दाल प्रति माह 1.5 कि0 ग्रा0 और खाद्य तेल प्रति माह 455 मिलीलीटर लाभार्थियो को वितरण किया जायेगा। वितरण दिवस को उक्त विकास खण्ड के ग्राम प्रधान/स्वयं सहायता समूह भी वितरण स्थल पर मौजूद रहेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकत्री के द्वारा उक्त वितरण दिनांक 15 व 16 अक्टूबर को किये जाने की सूचना ग्राम प्रधान/सभासद और अन्य जनप्रतिनिधियों को दिया जायेगा।

नेबुआ में सड़क हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल

नेबुआ नौरंगिया,कुशीनगर । हनुमानगंज थाना क्षेत्र के ग्राम सभा नरकहवा निवासी उमाशंकर कुशवाहा बीती शाम नेबुआ से घर लौटते समय सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार, नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के सेखुई गांव के समीप एक बाइक सवार को चपेट में आने से उमाशंकर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची नेबुआ नौरंगिया पुलिस ने घायल को सीएचसी कोटवा बाजार पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जांच के दौरान डॉक्टरों ने बताया कि घायल के कंधे और सिर की हड्डी टूट गई है, जिसकी गंभीरता को देखते हुए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। वर्तमान में वहां उनका इलाज चल रहा है, और चिकित्सकों के अनुसार उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। इस संबंध में एसएचओ नेबुआ नौरंगिया दिपक सिंह ने बताया कि घायल पक्ष की ओर से अभी कोई तहरीर नहीं मिली है।

भटनी में मिशन शक्ति फेज-5.0 व शक्ति दीदी अभियान चला

भटनी देवरिया।

छात्राओं व महिलाओं को विभिन्न स्थानों पर किया गया जागरूक

पुलिस अधीक्षक देवरिया संजीव सुमन के निर्देशन में दिन सोमवार को जनपद के सभी थानों में मिशन शक्ति फेज-5.0 एवं शक्ति दीदी अभियान के तहत व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रम चल रहा है । इसी क्रम में थाना भटनी क्षेत्र में प्रभारी निरीक्षक जितेन्द्र सिंह के नेतृत्व में मिशन शक्ति टीम के उप निरीक्षक,कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल द्वारा नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर महिलाओं, बालिकाओं और छात्र-छात्राओं को सुरक्षा व सशक्तिकरण के लिए जागरूक किया गया। टीम ने सुभाष इंटर कॉलेज भटनी, स्थानीय मंदिरों व सार्वजनिक स्थलों पर लोगों को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी, जिनमें डॉयल-112, हेल्पलाइन-181, वुमेन पावर लाइन-

1090, चाइल्ड हेल्प लाइन-1098, सीएम हेल्पलाइन-1076, वन स्टॉप सेंटर-181, स्वास्थ्य सेवा हेल्पलाइन-102 और एंबुलेंस सेवा-108 प्रमुख हैं। इस अवसर पर पम्पलेट वितरित कर छात्रों और

महिलाओं को किसी भी आपात स्थिति में इन हेल्पलाइन नंबरों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया गया।

दिल्ली में बुजुर्गों को लिफ्ट में फंसाकर ठगने वाले लिफाफा गैंग का भंडाफोड़, तीन बदमाश गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली के हर्ष नगर इलाके में पुलिस ने तीन ऐसे शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो लिफाफा गैंग के नाम से कुख्यात थे. ये गैंग बुजुर्ग नागरिकों खास तौर पर महिलाओं को कार में लिफ्ट देने के बहाने अपने जाल में फंसाता था और फिर उन्हें सम्मोहित करके उनके गहने एवं नकद के बदले नकली गहनों से भरा लिफाफा थमा कर फरार हो जाता था. इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रोशन (52 वर्ष), सागर (35 वर्ष) और दीपक (43 वर्ष) के रूप में हुई है. डीसीपी वेस्ट दराडे शरद भास्कर के मुताबिक, 18 जुलाई 2025 को एक महिला शिकायतकर्ता ने हरिनगर थाने में ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी. पीड़िता ने बताया कि तीन व्यक्तियों ने लिफ्ट देने के बहाने उसे कार में बैठाया और सम्मोहित कर उसके सोने के कान

के झुमके और 4,000 रुपये नकद ले लिए, जब वह घर पहुंची तो पाया कि उसके हाथ में दिए गए लिफाफे में असली गहनों की जगह नकली जेवर थे. ठगी के बढ़ते मामलों के मद्देनजर, एसीपी राजौरी गार्डन नीरज टोका की देखरेख और एसएचओ हरिनगर आशु गिरोत्रा के नेतृत्व में हरिनगर चौकी के इंचार्ज एसआई विक्रांत सिंह की एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें हेड कॉन्स्टेबल श्रीकृष्ण, पिंटू, घनश्याम, आनंद और कांस्टेबल मनोज, नारवीर, एवं मनीष शामिल थे.

आई10 कार और आधुनिक तकनीक से पकड़े गए आरोपी

टीम ने आरोपियों की तलाश में कई सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया और तकनीक की मदद से गाड़ी का पता लगाया. जांच में सामने आया कि अपराध में इस्तेमाल की गई i10 कार फर्जी नंबर प्लेट के साथ घूम रही थी. लगातार ट्रेस करने के बाद 11 अक्टूबर को पुलिस को सूचना मिली कि लिफाफा गैंग स्वर्ग आश्रम रोड की ओर जा रहा है. त्वरित प्रतिक्रिया करते हुए टीम ने ट्रैप लगाया और रात करीब 8:15 बजे संदिग्ध आई10 कार को रुकने का इशारा किया. ड्राइवर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने कार को घेर लिया और तीनों आरोपियों को दबोच लिया. कार की तलाशी में पुलिस को असली नंबर प्लेट, 22 कागजी लिफाफे, एक आर्टिफिशियल चेन, दो अंगूठियां और अन्य सामग्री बरामद हुईं, जिनका इस्तेमाल वे ठगी की वारदात में करते थे. पुलिस ने बरामद सामग्री के साथ कार को भी जब्त कर लिया. पूछताछ में तीनों ने एक अन्य मामले में भी अपनी संलिप्तता का खुलासा किया.

आईआरसीटीसी घोटाले में लालू-राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ आरोप तय

बीजेपी से आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा- तेजस्वी

नई दिल्ली।

बिहार में होने वाले हाई-वोल्टेज चुनाव से कुछ हफ्ते पहले राष्ट्रीय जनता दल के प्रथम परिवार को बड़ा झटका देते हुए, दिल्ली की एक अदालत ने आज पार्टी संस्थापक लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री व लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में आरोप तय किए।

वरिष्ठ नेता और उनके परिवार के सदस्यों ने खुद को निर्दोष बताया और कहा कि उन पर मुकदमा चलेगा। राउज़ एवेन्यू की एक अदालत ने आज लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक

साजिश से संबंधित धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय किए। लालू यादव और तेजस्वी यादव सहित अन्य ने खुद को निर्दोष बताया; राबड़ी देवी ने कहा कि मामला गलत है। वहीं, तेजस्वी ने इसको लेकर एक एक्स पोस्ट भी किया है। उन्होंने लिखा कि जब तक दंगाई एवं संविधान विरोधी बीजेपी सत्ता में है और मेरी उम्र है बीजेपी से लड़ते रहेंगे। तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। हमने संघर्ष पथ चुना है। संघर्ष पथ पर चलते-चलते अच्छे मुसाफिर बन

तेजस्वी बोले- शाह ने एक महीने पहले धमकी दी थी चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे

निश्चित ही मंजिल प्राप्त करेंगे। राजद नेता ने आगे कहा कि एक महीना पहले बिहार आकर गृहमंत्री अमित शाह जी हमें धमकी दे रहे थे कि हमको चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हम बिहारी है बिहारी, बाहरी से नहीं डरते। जय बिहार, जय बिहारी! यह मामला लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए रांची और पुरी स्थित दो आईआरसीटीसी होटलों के टेंडर में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है।

विशेष न्यायाधीश (सीबीआई) ने पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। वे अदालत में प्रत्यक्ष रूप से पेश हुए। अदालत ने धोखाधड़ी, षड्यंत्र और भ्रष्टाचार से जुड़े अपराधों की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं। हालांकि, सभी आरोपियों पर आपराधिक षड्यंत्र का आरोप लगाया गया है। यह आदेश खुली अदालत में सुनाया गया और अदालत एक विस्तृत आदेश अपलोड करेगी। अदालत ने कहा कि सभी 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त आधार है। लालू प्रसाद यादव ने खुद को निर्दोष बताया है और कहा है कि वह मुकदमे का सामना करेंगे।

राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका, वोट चोरी के आरोपों पर दायर याचिका खारिज

नई दिल्ली।

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोपों की जांच के लिए दायर एक जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि ऐसे मामलों की जांच करना न्यायपालिका का नहीं, बल्कि ईसीआई का अधिकार क्षेत्र है। अधिवक्ता रोहित पांडे ने एक जनहित याचिका दाखिल की थी।

इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया था कि वह पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयानों - जिनमें उन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाया था - की जांच के लिए एक विशेष जांच दल गठित करने का निर्देश दे। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की दो सदस्यीय बेंच ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को ईसीआई के पास जाने की सलाह दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया या परिणामों से जुड़ी शिकायतों की जांच का अधिकार केवल निर्वाचन आयोग को है और न्यायपालिका का इसमें सीधा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलों को सुनने के बाद कहा कि इस मामले में जनहित याचिका का कोई औचित्य नहीं बनता है और इसे खारिज कर दिया जाता है।

कोर्ट के इस निर्देश के साथ ही, राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों को लेकर एसआईटी जांच की मांग अब समाप्त हो गई है।

ममता बनर्जी ने उत्तर बंगाल में बाढ़ के लिए भूटान को जिम्मेदार ठहराया, मुआवजे की मांग की

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को दावा किया कि उत्तर बंगाल में हाल ही में आई बाढ़ भूटान से छोड़े गए पानी के कारण आई है। बनर्जी ने बाढ़ के कारण हुई क्षति और जान-माल की हानि के लिए हिमालयी राज्य से मुआवजे की भी मांग की। एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान दिए गए संक्षिप्त संबोधन में बनर्जी के हवाले से कहा भूटान से आने वाले पानी के कारण हमें नुकसान हुआ है... हम चाहते हैं कि वे हमें मुआवजा दें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को सभी राहत और पुनर्वास की व्यवस्था करनी है और दावा किया कि केंद्र इसके लिए भुगतान नहीं करता है। मुख्यमंत्री के अनुसार, उनकी सरकार लंबे समय से एक भारत-भूटान नदी आयोग के गठन की मांग कर रही है जिसमें पश्चिम बंगाल को भी सदस्य बनाया जाना चाहिए। बनर्जी ने कहा कि इस मुद्दे पर 16 अक्टूबर को एक बैठक होने की संभावना है और राज्य अपने प्रतिनिधि के रूप में एक अधिकारी भेजेगा।

माँ, माटी, मानुष का दावा झूठा! बांसुरी स्वराज बोलीं- सीएम ममता बनर्जी के कुशासन से बंगाल में माँ शर्मिंदा

बंगाल।

दुर्गापुर में द्वितीय वर्ष की मेडिकल छात्रा के साथ कथित सामूहिक बलात्कार मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए, भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने सोमवार को कहा कि यह सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की रूढ़िवादी मानसिकता को दर्शाता है। बयान को असंवेदनशील बताते हुए, स्वराज ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देवी दुर्गा की भूमि माने जाने वाले राज्य में महिलाएं असुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि माँ दुर्गा के बंगाल में महिलाएं असुरक्षित हैं। राज्य की महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बलात्कार पीड़िता को दोषी ठहराकर ऐसी असंवेदनशील टिप्पणी करती हैं। मेरा मानना है कि यह टीएमसी की रूढ़िवादी मानसिकता को दर्शाता है।

स्वराज ने बनर्जी से ओडिशा की रहने वाली पीड़िता को न्याय दिलाने और राज्य भर में महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाने पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। उन्होंने आगे कहा, मैं ममता बनर्जी से कहना चाहूँगी कि वह न केवल राज्य की मुख्यमंत्री हैं, बल्कि गृह विभाग भी उनके पास है। इसका मतलब है कि आंतरिक सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी उनकी है। उन्हें ऐसा

राज्य की महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बलात्कार पीड़िता को दोषी ठहराकर ऐसी असंवेदनशील टिप्पणी करती हैं। मेरा मानना है कि यह टीएमसी की रूढ़िवादी मानसिकता को दर्शाता है।

माहौल बनाना चाहिए जहाँ लड़कियाँ सुरक्षित महसूस करें और दिन हो या रात, आज़ादी से घूम सकें। मैं उनसे फिर से अनुरोध करना चाहूँगी कृपया बलात्कार को सही न ठहराएँ। उस लड़की को न्याय दिलाने की दिशा में काम करें। स्वराज ने आगे कहा कि मैं ममता बनर्जी से पूछना चाहती हूँ, वे माँ, माटी, मानुष के नारे लगाती हैं। लेकिन आपकी असंवेदनशीलता, कुशासन और प्रतिगामी मानसिकता के कारण आज बंगाल में माँ शर्मिंदा है, माटी लहूलुहान है और मानुष बदहाल है। इस बीच, राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की सदस्य अर्चना मजूमदार ने एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष रेखा शर्मा के स्वतः संज्ञान लेने के निर्देश के बाद मामले की चल रही जाँच की समीक्षा के लिए दुर्गापुर का दौरा किया। उन्होंने पीड़िता के परिवार, छात्रों और स्थानीय अधिकारियों, जिनमें एसपी और ओसी भी शामिल हैं, से मुलाकात की। उन्होंने एक समाचार एजेंसी को बताया, मेरी अध्यक्ष से बातचीत हुई। उन्होंने मुझे मामले का तुरंत स्वतः संज्ञान लेने, घटनास्थल पर पहुँचने और पीड़िता से मिलने के लिए कहा। मैंने अधिकारियों, छात्रों और पीड़िता के अभिभावकों से बात की। फिर मैंने पुलिस, एसपी और ओसी से बात की। हम अगले कार्यदिवस पर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। उन्होंने आगे बताया कि पुलिस ने पाँच संदिग्धों की पहचान कर ली है, जिनमें से तीन को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस जल्द से जल्द आरोप पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया में है। मेडिकल नमूने राज्य फोरेंसिक प्रयोगशाला भेजे गए हैं, जिन्हें उन्होंने केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) भेजने की सिफारिश की है।

जनसुराज की दूसरी लिस्ट जारी, 65 सीटों पर उतारे प्रत्याशी

पटना। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पार्टी ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि हमने पहले ही कहा था कि समाज में जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, उन्हें उतनी ही हिस्सेदारी मिलेगी। बिहार में अतिपिछड़ा समाज के लोगों की संख्या सबसे अधिक है।

इसीलिए हमलोगों ने अब तक एक तिहाई सीटों पर इन्हें ही टिकट दिया है। आज दूसरी लिस्ट में 65 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई है। इससे पहले 51 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई थी। अब तक 116 प्रत्याशी के नाम की घोषणा की गई है। इसमें सबसे अधिक संख्या अतिपिछड़ा समाज के लोगों की है। पीके ने कहा कि बिहार के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी राजनीतिक दल ने इतने अधिक संख्या में अतिपिछड़ों को टिकट दिया है। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने 65

उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। इससे पहले जनसुराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपने पहले 51 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में 7 सुरक्षित और 44 सामान्य सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। पार्टी ने जातीय संतुलन का ध्यान रखते हुए अति पिछड़ा वर्ग से 17 (16 हिंदू और 1 मुस्लिम), अन्य पिछड़ा वर्ग से 11, सामान्य वर्ग से 9 और अल्पसंख्यक वर्ग से 7 उम्मीदवार उतारे हैं। इसके अलावा, वाल्मीकिनगर विधानसभा सीट से एक अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार को टिकट दिया गया है।

हर नागरिक की सेवा, सुरक्षा और सम्मान करना सरकार का मुख्य उद्देश्यः सीएम योगी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को जनता दर्शन कार्यक्रम में फरियादियों की शिकायतें सुनीं और अधिकारियों को हर मामले का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, विभिन्न जिलों से आये 50 से अधिक फरियादियों ने पुलिस कार्रवाई, बिजली आपूर्ति, वित्तीय सहायता और भूमि विवाद से संबंधित शिकायतें और निवेदन सामने रखे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर फरियादी से बातचीत की। उनके आवेदन प्राप्त किये और अधिकारियों को उनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। आदित्यनाथ ने जनता की सेवा, सुरक्षा और सम्मान के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि यह सिद्धांत उनकी सरकार के गठन के पहले दिन से ही उसका मार्गदर्शन करता रहा है। बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी ने शिकायतकर्ताओं के साथ आए बच्चों से भी बातचीत की, उनके सिर पर हाथ फेरा, उन्हें चॉकलेट और टॉफियां दीं और उन्हें खूब पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित किया।

लद्दाख के लोगों से किए वादे से पीछे हट रही है भाजपा - जयराम रमेश

नई दिल्ली। कांग्रेस ने सोमवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने लद्दाख को छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा देने का वादा किया था, लेकिन अब उसे पूरा करने से पीछे हट रही है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना के भारत दौरे का उल्लेख करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। रमेश ने 'एक्स पर पोस्ट किया, मंगोलिया के राष्ट्रपति आज एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ नयी दिल्ली पहुंच चुके हैं। भारत और मंगोलिया के बीच राजनयिक संबंध दिसंबर 1955 में स्थापित हुए थे। भारत ने अक्टूबर 1961 में मंगोलिया को संयुक्त राष्ट्र में शामिल कराने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा, इस रिश्ते में निर्णायक मोड़ तब आया, जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अक्टूबर 1989 में लद्दाख के अत्यंत लोकप्रिय एवं सम्मानित बौद्ध भिक्षु 19वें कुशोक बकुला रिनपोछे को मंगोलिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया। उन्होंने जनवरी 1990 में पदभार संभाला और असामान्य रूप से दस वर्षों तक वहाँ भारत के राजदूत रहे। रमेश के अनुसार, 1990 में साम्यवाद के पतन के बाद मंगोलिया को उसकी बौद्ध विरासत से दोबारा जोड़ने और उसे पुनर्जीवित करने में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। उनका कहना है कि मंगोलिया में आज भी रिनपोछे को एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के रूप में सम्मानपूर्वक स्मरण किया जाता है। कांग्रेस महासचिव ने कहा, 10 जून 2005 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने लेह

हवाई अड्डे का नाम बदलकर कुशोक बकुला रिनपोछे हवाई अड्डा रखा और उन्हें आधुनिक लद्दाख के शिल्पकार के रूप में सम्मानित किया। रमेश ने कहा, बौद्ध धर्म का पुनर्जागरण- न केवल मंगोलिया और पूर्व सोवियत संघ में, बल्कि भारत में भी -काफी हद तक रिनपोछे के प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने कहा, आज 19वें कुशोक बकुला रिनपोछे का लद्दाख, देश से मरहम की प्रतीक्षा कर रहा है, खास तौर पर उस पार्टी के नेतृत्व से जिसने 2020 के स्थानीय पर्वतीय परिषद के चुनावों के अपने घोषणापत्र में छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा का वादा किया था, लेकिन अब वह सत्ता में हो कर भी उसे पूरा करने से पीछे हट रही है।

ओमप्रकाश राजभर बीजेपी से हुए खफा, अब बिहार में अकेले लड़ेंगे विधानसभा चुनाव

पटना। भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) ने बिहार विधानसभा चुनाव में राजग द्वारा एक भी सीट नहीं दिए जाने के बाद 153 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार में भी शामिल सुभासपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर ने सोमवार को कहा कि भाजपानीत राजग ने उनकी पार्टी को बिहार विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं दी है, लिहाजा उनकी पार्टी बिहार में 153 सीट पर चुनाव लड़ेगी। उम्मीदवारों की घोषणा मंगलवार को पटना में प्रेस कांफ्रेंस कर की जाएगी। सुभासपा के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण एवं पंचायती राज मंत्री हैं। ओमप्रकाश के पुत्र और पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर ने मंगलवार को बलिया जिले के बेल्थरारोड क्षेत्र में एक कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं

से कहा, हम बिहार में पिछले 19 साल से अपने संगठन को बढ़ा रहे हैं। पार्टी विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए शक्ति प्रदर्शन करती रही है। हमारा प्रयास था कि उत्तर प्रदेश में हम राजग के साथ हैं तो बिहार में भी उसे मजबूत करें। उन्होंने कहा, ''बिहार के भाजपा के स्थानीय संगठन ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बारे में विपरीत रिपोर्ट दी जिसकी वजह से राजग ने हमें एक भी सीट नहीं दी। उन्होंने कहा, हम बहुत पहले से कह भी रहे थे और पिछली एक मई को गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा को भी बता दिया था। कल तक हमने प्रतीक्षा की कि हमारी बात बन जाए लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब हमने यह तय किया है कि हम बिहार में 153 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। राजभर ने बताया कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से पांच सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव मिला था जिसे पार्टी नेतृत्व ने ठुकरा दिया है। उन्होंने बताया, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कल रात बात हुई है। तेज प्रताप यादव से भी बातचीत हुई है। कल पटना में प्रेस कांफ्रेंस कर बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे। राजभर ने एक सवाल के जवाब में स्पष्ट किया है कि वह उत्तर प्रदेश में राजग के साथ रहेंगे। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा, बिहार में हम किसी को हराने या जिताने नहीं जा रहे हैं। हम अपने वोट को इकट्ठा करेंगे। कोई हार जाए अथवा जीत जाए, इसकी हमको परवाह नहीं है।

करूर भगदड़ की होगी सीबीआई जांच, सुप्रीम कोर्ट का आदेश; एक्टर विजय की रैली में हुई थी 41 लोगों की मौत

नई दिल्ली।

तमिलनाडु के करूर में अभिनेता से नेता बने विजय की रैली में मची भगदड़ से 41 लोगों की मौत हो गई। तमिलनाडु सरकार और मद्रास हाईकोर्ट के बाद अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सर्वोच्च न्यायालय ने भगदड़ की सीबीआई जांच करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट को भी फटकार लगाई है। अदालत का कहना है कि जब मामला पहले से मदुरै कोर्ट में चल रहा था, तो मद्रास हाईकोर्ट ने बीच में हस्तक्षेप क्यों किया?

तमिलनाडु सरकार से पूछा सवाल

करूर भगदड़ पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से भी सवाल पूछे हैं। सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि राज्य सरकार ने कम जगह का हवाला देते हुए करूर में 10 अक्टूबर को AIADMK को रैली करने की इजाजत नहीं दी थी। ऐसे में 27 अक्टूबर को विजय की पार्टी TVK को रैली की अनुमति कैसे मिल गई?

मद्रास हाईकोर्ट को लगाई फटकार

वहीं, मद्रास हाईकोर्ट से सवाल पूछते हुए जस्टिस महेश्वरी ने कहा, मैंने अपने 15 साल के करियर में ऐसा पहले कभी नहीं देखा कि जो मामला डिवीजन बेंच में चल रहा

है, उसपर मद्रास हाईकोर्ट की एक जज की बेंच ने SIT जांच का आदेश कैसे दे दिया?

कमेटी बनाने का आदेश

CBI जांच के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यों की कमेटी बनाने का भी आदेश दिया है, जो जांच पर नजर रखेगी।

इस कमेटी की अध्यक्षता पूर्व जस्टिस अजय रस्तोगी करेंगे। वहीं, कमेटी में IGP रैंक वाले तमिलनाडु कैडर के 2 IPS अधिकारी भी मौजूद होंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा–

कमेटी CBI जांच की निगरानी करेगी। साथ ही भगदड़ केस की भी जांच की जाएगी। वहीं, जरूरत पड़ने पर यह कमेटी किसी भी समय सुप्रीम कोर्ट से संपर्क कर सकती है। साथ ही CBI को हर महीने कमेटी के सामने जांच रिपोर्ट पेश करनी होगी।

करूर भगदड़

बता दें कि एक्टर विजय की रैली में अचानक मची भगदड़ से 41 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे की सटीक वजह अभी सामने नहीं आई है। मगर भगदड़ का कारण भीड़ हो सकती है। पुलिस के अनुसार, करूर के मैदान की क्षमता महज 10 हजार लोगों की थी, लेकिन रैली में 30 हजार के लगभग लोग पहुंच गए। रैली का समय सुबह के लिए निर्धारित किया गया था, हालांकि विजय 7 घंटे की देरी से शाम को रैली में पहुंचे, जिससे भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ देखने को मिली।